RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 353
दि. 26.04.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

काशी से पीएम मोदी दो ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी, दोनों ही ट्रेनें यूपी से महाराष्ट्र को जोड़ेंगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से पुणे के हडपसर तक अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, जो प्रतिदिन संचालित होगी।

पीएम मोदी बनारस से पुणे के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, यूपी-महाराष्ट्र को जोड़ेंगी दो नई ट्रेनें।

पीएम मोदी ने बनारस-पुणे अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई।

यह ट्रेन बनारस से हडपसर (पुणे) तक प्रतिदिन चलेगी।

यूपी-महाराष्ट्र को जोड़ने वाली दो नई ट्रेनें शुरू हुई।

वाराणसी। (जीएनएस)। पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उद्घाटित अमृत भारत एक्सप्रेस अब पुणे जनपद के हडपसर रेलवे स्टेशन तक यात्रा करेगी। रेलवे बोर्ड के निदेशक कोचिंग संजय आर नीलम ने इस ट्रेन का शेड्यूल जारी किया है। यह ट्रेन बनारस-पुणे-बनारस के बीच संचालित होगी और इसकी पहचान नंबर 22589/22590 होगी।

यह 22 कोचों वाली अमृत भारत एक्सप्रेस बनारस रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन शाम सवा छह बजे रवाना होगी और 30 घंटे बाद, यानी तीसरे दिन रात 12:10 बजे हडपसर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। वापसी यात्रा में, यह ट्रेन दिन में ढाई बजे हडपसर से चलकर सुबह 07:50 बजे बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।

भदोही जिले के निवासियों को भी इस ट्रेन से लाभ होगा, क्योंकि इसका पहला ठहराव ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर होगा। वर्तमान में ज्ञानपुर से सप्ताह में दो दिन, बुधवार (22132

ज्ञानगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस) और शनिवार (11034 दरभंगा-पुणे एक्सप्रेस) गुजरती है। अमृत भारत एक्सप्रेस ज्ञानपुर से यात्रा करने वाली पहली नियमित ट्रेन होगी।

यात्रियों को इस ट्रेन से यात्रा करने के लिए निम्नलिखित 20 रेलवे स्टेशनों पर रुकने का अवसर मिलेगा: बनारस, ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज, फतेहपुर, गोविंदपुरी, ओराई, झांसी, बीना, रानी कमलापति, नर्मदापुरम, ईटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल, जलगांव, मनमाड, रोपर गांव, अहिल्याबाई नगर, डाउंड कोर्ड लाइन और हडपसर रेलवे स्टेशन (पुणे)।

इस ट्रेन के संचालन से न केवल बनारस बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी यात्रा में सुविधा मिलेगी। यह ट्रेन यात्रियों के लिए एक नई और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प प्रस्तुत करेगी। वहीं दूसरी ट्रेन अयोध्या से मुंबई के लिए शुरू की गई है। दोनों ही ट्रेनें महाराष्ट्र को जोड़ेंगी। इन दोनों ही ट्रेनों के शुरू होने की वजह से यूपी का महाराष्ट्र से सीधा जुड़ाव हो सकेगा। यह ट्रेन न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव भी प्रदान करेगी।

जादवपुर यूनवर्सिटी को पीएम मोदी ने बताया 'अराजकता का अड्डा', ममता बनर्जी बोलीं, 'ये एक्सीलेंस है'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जादवपुर यूनिवर्सिटी को अराजकता का अड्डा बताया, जिस पर ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई. उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी की आलोचना की.

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच जादवपुर यूनिवर्सिटी (JU) को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम ममता बनर्जी आमने-सामने आ गए. पीएम मोदी ने प्रदेश की टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके शासनकाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी अराजकता का अड्डा बन गया है. पहले इसकी दुनिया भर में इज्जत थी और यह राष्ट्रवाद की नींव पर बना था. PM मोदी ने कहा कि जो सरकार इस यूनिवर्सिटी को नहीं बचा पाई वो बंगाल क्या बचाएगी? ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे विश्वविद्यालय के छात्रों का अपमान बताते हुए कहा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र मेहनत से अपनी जगह बनाते हैं. सवाल पूछते हैं. सोचने-समझने की क्षमता रखते हैं. ये अराजकता नहीं है बल्कि एजुकेशन और एक्सीलेंस है.

अपि१३रीॅल्ल३

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 को जादवपुर विधानसभा

क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे. इस दौरान एक रैली में मोदी ने कहा कि पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी (खव) की दुनिया भर में इज्जत थी. यह राष्ट्रवाद की नींव पर बना था लेकिन अब कैंपस के अंदर धमकियां मिलती हैं. दीवारों पर देश-विरोधी नारे लिखे जा रहे हैं और छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय सड़कों पर विरोध करने के लिए मजबूर किया जाता है. पीएम ने कहा,

हमें यहां अराजकता नहीं, बल्कि पढ़ाई का अच्छा माहौल चाहिए. जो सरकार इस यूनिवर्सिटी को 'बचा' नहीं पाई, क्या वह राज्य का भविष्य बचा पाएगी?

बता दें कि जादवपुर यूनिवर्सिटी देश और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती रही है. ममता बनर्जी और यूनिवर्सिटी के बीच रिश्ते कई बार टेंशन वाले रहे हैं. यहां के छात्रों ने ममता सरकार की आलोचना भी की है. फिर भी पीएम मोदी के बयान के बाद ममता बनर्जी ने तुरंत यूनिवर्सिटी का बचाव किया. उन्होंने कहा,

जादवपुर यूनिवर्सिटी के होनहार छात्रों को आप इस तरह का बताते हैं? यहां के छात्र अपनी मेहनत से जगह बनाते हैं. डिग्री लेते हैं. सोचने-समझने की क्षमता रखते हैं और सवाल पूछते हैं. यह अराजकता नहीं है बल्कि शिक्षा और उत्कृष्टता है.

ममता बनर्जी ने आगे कहा कि जिसे पीएम मोदी अराजकता कह रहे हैं, वो असल में लोकतंत्र का हिस्सा है. बुलडोजर पॉलिटिक्स, धर्म के नाम पर देश को बांटना और मीडिया का सामना न करना ये असली अराजकता है. ममता ने एक रैली में यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी अपील की कि वह मोदी के बयान का विरोध करें.

बता दें कि NIRF 2025 रैंकिंग में जेयू पूरे भारत की यूनिवर्सिटीज में 9वें स्थान पर रही थी. टॉप 10 में आने वाली यह इकलौती स्टेट यूनिवर्सिटी थी. यह राज्य पब्लिक यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहले स्थान पर और ओवरऑल में 18वें स्थान पर रही.

गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र... पीएम मोदी को हर जगह जाने का अधिकार, हिमंत बिस्वा सरमा का ममता पर पलटवार

(जीएनएस)।

हिमंत ने बंगाल चुनाव को लेकर एक बड़ा और अहम दावा किया है. उन्होंने कहा कि असम में पहले चुनाव के दौरान भारी अफरातफरी मचती थी. लेकिन आज असम में हर चुनाव एक बहुत बड़े उत्सव की तरह होता है. बंगाल में भी चुनाव का दूसरा चरण एक बड़े उत्सव जैसा ही चल रहा है. पहले चरण में बहुत अच्छी वोटिंग हुई और कोई भी अफरातफरी नहीं मची.

उत्तर 24 परगना. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भाजपा उम्मीदवार सुदीप्ता दास के समर्थन में एक रोड शो किया. इस कार्यक्रम में भाजपा के कई कार्यकर्ता

और समर्थक शामिल हुए. यह रोड शो नोआपारा पुलिस स्टेशन से शुरू होकर कांचरापाड़ा बाग मोड़ तक गया.

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जाएंगे. प्रधानमंत्री को हर जगह जाने का अधिकार है. दीदी को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. पूरी दुनिया ने देखा कि बंगाल की पर्यटन क्षमता बढ़ गई है. जब प्रधानमंत्री असम आते हैं तो मैं खुले दिल से उनका स्वागत करता हूं. दीदी, जो कुछ भी बंगाल के लिए अच्छा होता है, वह उसका विरोध करती हैं.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाया तो पूरा देश झालमुड़ी पर फिदा हो गया है. यह बंगाल के लिए अच्छा हुआ या नहीं हुआ. इससे लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं. ऐसे में ममता दीदी, प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर रही हैं, वो बांग्ला का विरोध कर रही हैं. हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम में एक समय ऐसा था, जब चुनावों के दौरान काफी अफरा-तफरी मची रहती थी, लेकिन आज असम में चुनाव एक उत्सव की तरह है. मेरा मानना है कि बंगाल में चुनाव का दूसरा चरण भी एक उत्सव जैसा ही है. यही वजह है कि पहले चरण में अच्छी वोटिंग हुई. कोई अफरा-तफरी नहीं मची, लोगों ने बढ़-चढ़कर मतदान किया।

इसीलिए दूसरे चरण में लोगों का उत्साह दोगुना हो गया है. सीएम सरमा ने कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी.

23 अप्रैल को भी हिमंत बिस्वा सरमा ने उत्तर 24 परगना के बोंगागांव निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया था. उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा था कि मतुआ समाज ने शुरूआत से ही भाजपा का साथ दिया है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बार भी मतुआ समाज भाजपा के साथ है. मछली खाने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि असम में भाजपा की सरकार है. असम में भी लोग मांस-मछली खाते हैं. उन्होंने कहा कि मैं तो ममता बनर्जी से ज्यादा मांस खा जाऊंगा.

लखनऊ पीजीआई में प्रदेश के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट की मरीज स्वस्थ, आज होगी छुट्टी; डिप्टी सीएम डॉक्टरों को करेंगे सम्मानित

लखनऊ। संजय गांधी पीजीआई में किए गए प्रदेश के पहले हृदय प्रत्यारोपण की मरीज स्वस्थ है। महिला रोगी बातचीत करने के साथ भोजन और बिना किसी के सहारे चल फिर रही है।

डॉक्टर शनिवार को छुट्टी करेंगे। इस मौके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह व मुख्य सचिव एसपी गोयल, संस्थान निदेशक डॉ. आरके धीमन समेत शासन के अफसर हृदय प्रत्यारोपण करने वाली टीम के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करेंगे।

पीजीआई के सीवीटीएस विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. एसके अग्रवाल ने बताया कि 12 अप्रैल को संस्थान में प्रदेश का पहला हृदय प्रत्यारोपण कर एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है।

डॉक्टरों ने दिल्ली से विशेष एयर एम्बुलेंस से लाया गया दिल सीतापुर निवासी दिल की मांसपेशियों की गंभीर बीमारी से पीड़ित 43 वर्षीय महिला में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया था।

चिलचिलाती गर्मी बनी मुसीबत... हरिद्वार, लखनऊ में बदली गई स्कूलों की टाइमिंग, कई राज्यों में छुट्टियों का ऐलान

भीषण गर्मी और लू को देखते हुए गाजियाबाद, लखनऊ, हरिद्वार सहित कई जगहों पर स्कूलों का समय बदल दिया गया है. अधिकतर जगह स्कूलों का समय अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कर दिया गया है. छत्तीसगढ़, एमपी और ओडिशा राज्य में समय से पहले ही स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं. भारत के कई राज्य इस समय भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में हैं. बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए भारत के विभिन्न राज्यों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. यहां तक की कुछ में समय से पहले छुट्टियों की घोषणा कर दी है. हीटवेव की चेतावनी, हरिद्वार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने पूरे जिले में स्कूलों के समय में बदलाव करने के निर्देश जारी किया है.

आदेश में कहा गया है, 27 अप्रैल से 26 मई तक, सभी प्री-प्राइमरी से क्लास 5 तक के स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक चलेंगे. जबकि क्लास 6 से 12 तक के स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे. ये कदम बच्चों के स्वस्थ को देखते हुए उठाया गया है.

उत्तराखंड की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी स्कूल के समय में बदलाव किया गया है. बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों (कक्षा 1 से 8) का समय बदलकर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कर दिया है.

बिहार में भी इस समय गर्मी ने सबको परेशान कर रखा है. गर्मी के कारण बच्चों की सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े इसको देखते हुए पटना, गया, और औरंगाबाद सहित कई जिलों में 5वीं तक की कक्षाएं दोपहर 12:30 बजे तक कर दी गई हैं. वहीं सारण (छपरा) में 5वीं तक के स्कूल सुबह 11:30 बजे तक ही चल रहे हैं.

दिल्ली और लखनऊ आरएसएस कार्यालय आतंकियों के निशाने पर, नोएडा से पकड़े गए दहशतगर्दों की ग्रेनेड अटैक की थी साजिश

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश एटीएस ने नोएडा और बिजनौर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों के मंसूबे इतने खतरनाक थे कि वे देश की राजधानी दिल्ली और यूपी की राजधानी लखनऊ को दहलाने की साजिश रच रहे थे। जांच में सामने आया है कि इन आतंकियों के निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यालय थे, जहां वे हैंड ग्रेनेड से हमला करने की तैयारी में थे। नोएडा से गिरफ्तार किए गए इन दो आतंकियों के नाम हैं तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान और समीर खान। दोनों ने पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक, इन दोनों को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट ने दिल्ली और लखनऊ

पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे

स्थित आरएसएस कार्यालयों पर धमाका करने का लक्ष्य दिया था।

आतंकियों के पास से दिल्ली और लखनऊ के महत्वपूर्ण ठिकानों के नक्शे बरामद हुए हैं। हिजबुल्ला ने स्वीकार किया है कि उसने संघ के कार्यालयों की रेकी भी की थी। हिजबुल्ला मूल रूप से एक हिंदू परिवार से है। वो इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में आया था। भट्टी ने उसका ब्रेनवॉश किया और उसे इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उसने अपना नाम हिजबुल्ला अली खान रख लिया। इनके मोबाइल फोन से कई महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की तस्वीरें भी मिली हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि इनके निशाने पर कई वीआईपी ठिकाने थे। एटीएस की कार्रवाई केवल नोएडा

तक सीमित नहीं रही। बिजनौर से भी दो संदिग्ध आतंकियों जुल्फिकार उर्फ राका और आरिफ मलिक को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने विशेष रूप से आगजनी के जरिए दहशत फैलाने का काम सौंपा था। इससे पहले 3 अप्रैल को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से साकिब, अरबाब, लोकेश और विकास गहलावत को पकड़ा गया था। इन्हीं से पूछताछ के आधार पर बिजनौर और नोएडा के नेटवर्क का पता चला।

जांच में एक वीडियो सामने आया है जिसमें दुबई में बैठा आकिब नामक शख्स AK-47 और हैंड ग्रेनेड लेकर ग्रुप कॉल पर इन आतंकियों से बात कर रहा था। पुलिस की सक्रियता देख आकिब ने जुल्फिकार को व्हाट्सएप कॉल कर सारे सबूत डिलीट करने का निर्देश भी दिया था। यह पूरा मॉड्यूल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टरों के समन्वय से चल रहा था।

उपराष्ट्रपति ने राजस्थान विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में युवाओं से रोजगार सृजनकर्ता और राष्ट्र निमार्ता बनने का आग्रह किया

(जीएनएस)।

भारत के उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने आज जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में राजस्थान को समृद्ध विरासत, वीरता और गहरी सांस्कृतिक विरासत की भूमि बताया जिसने लंबे समय से उत्कृष्टता और चरित्र को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि जयपुर विरासत और प्रगति का एक जीवंत प्रतीक है और राजस्थान विश्वविद्यालय ज्ञान, सत्यनिष्ठा और सेवा के प्रति समर्पित विचारकों, नेताओं और परिवर्तनकताओं की पीढ़ियों को आकार देना जारी रखे हुए है।

उपराष्ट्रपति ने स्नातक छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह एक अंत और एक नई शुरूआत दोनों का प्रतीक है। उन्होंने छात्रों से अपने ज्ञान को प्रगति के साधन के रूप में उपयोग करने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का वास्तविक महत्व समाज की बेहतरी, नवाचार और नैतिक आचरण के लिए इसके प्रयोग में निहित है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के

नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए, उन्होंने स्नातकों को रोजगार सृजनकर्ता, नवप्रवर्तक और राष्ट्र निमार्ता बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में युवाओं के लिए नवाचार और अवसरों को बढ़ावा देने के प्रयासों की भी सराहना की।

महिला सशक्तिकरण के महत्व पर जोर देते हुए, उपराष्ट्रपति ने महिला स्नातकों की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में स्वर्ण पदक जीतने वालों में अधिकांश महिलाएं रही हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए समान अवसर, गरिमा और नेतृत्व की भूमिका के बिना एक सच्चा विकसित राष्ट्र अस्तित्व में नहीं रह सकता। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को और अधिक बढ़ाएगा।

तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हुए, उपराष्ट्रपति ने छात्रों से आलोचनात्मक चिंतन करने, नैतिक आचरण अपनाने और आजीवन सीखने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों को दृढ़ रहने, असफलताओं से सीखने और मूल्यों पर अडिग रहने के लिए प्रेरित किया, और कहा कि सहानुभूति के बिना उत्कृष्टता और विनम्रता के बिना उपलब्धि अधूरी है।

उन्होंने स्नातकों से समाज में सार्थक योगदान देने, करुणा का भाव रखने, विविधता का सम्मान करने और सार्वजनिक हित के लिए काम करने का आ'ान किया। उन्होंने स्नातकों से नशे से दूर रहने और सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग करने की भी सलाह दी।

इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ किसानराव बागडे; उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा; संसद सदस्य (राज्यसभा) डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल; और राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा उपस्थित थी।

सम्पादकीय

अशोक लाहिड़ी बने नीति आयोग के सदस्य

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग का पुनर्गठन हुआ है और इसमें अशोक लाहिड़ी को वाइस चेयरमैन तथा जिन पांच पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति हुई है उनमें सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री केवी राजू, एम्स के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय करंदीकर, पूर्व वैबिनेट सचिव राजीव गाबा और वैज्ञानिक गोवर्धन दास शामिल हैं। जिन लोगों को नीति आयोग में स्थान मिला है वे सभी अपने-अपने क्षेत्र में सक्षम और विशेषज्ञ हैं। किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि इस आयोग में वृषि वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री नहीं हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार वृषि है और वृषि के क्षेत्र की समस्याओं और उसके विकास के लिए कोई भी विशेषज्ञ पूर्णकालिक रूप से शामिल न किया जाना इस बात का परिचायक है कि किसान कल्याण और वृषि को उद्योग का दर्जा देने में सरकार कितनी गंभीर है। रही बात शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं एवं नई चुनौतियों की तो नीति आयोग में इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

हैरानी की बात तो यह है कि नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर हुआ है। जिस तरह से योजना आयोग थिक टैंक क्लब बनकर रह गया था बिल्वुल उसी तरह नीति आयोग भी व्यावहारिकता से दूर बौद्धिक व्यायाम करने वालों का क्लब बन चुका है। जिनकी शिक्षा-दीक्षा, रहन-सहन सब वुछ भारतीयता से परे है।

आज भारत में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वित्तीय, विपणन, मानव संसाधन से लेकर वृषि, खनिज, रक्षा एवं एआई के क्षेत्र में प्रगति ही नहीं बल्कि संतुलित विकास की जरूरत है। हमें अपने बाजार को आकर्षक तो बनाने की जरूरत है ही साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादकता को आज की तुलना में कई गुना ज्यादा भी करना है। यह सब शहरी क्षेत्र से जुड़े बौद्धिक से संभव नहीं होगा बल्कि इसके लिए उन लोगों की सलाह एवं मार्ग दर्शन की जरूरत है जो जमीनी स्तर पर अपने-अपने क्षेत्रों में काम कर चुके हों। खुद आज के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो योजना आयोग पर तंज कसते हुए कहा था कि यह संस्था बिल्वुल हवा हवाई और अतार्विक है। वे एक घटना का उल्लेख करते हैं कि उनके राज्य में शेर के लिए कम और चीता के लिए ज्यादा राशि का आवंटन हुआ तो उन्होंने योजना आयोग से पूछा था कि क्या शेर कम्यूनल है उसे कम और चीता सेक्युलर है इसलिए आवंटन की राशि कम ज्यादा कर दी गई है।

बहरहाल नीति आयोग एक दिशा-निर्देशन की सबसे बड़ी सरकारी संस्था है। इसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठवें करके विकास की रूप रेखा लिखते हैं और सवार्गीण विकास के लिए ऐसी व्यावहारिक नीतियां बनाते हैं जिन्हें आसानी से लागू किया जा सके। किन्तु दुर्भाग्य से यह संस्था आज उतनी उपयोगी साबित नहीं हो पाई जितना कि गांव, गरीब और गांधी के सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। उम्मीद है कि नीति आयोग की सलाह और यथार्थ के बीच व्यावहारिकतापूर्ण संतुलन स्थापित करने की जरूरत जरूर महसूस की जाएगी। नीति आयोग की प्रथमिकताएं तभी बदलेंगी जब इसे पैर के बल खड़ा किया जाएगा। अभी तो यह सिर के बल खड़ी है। उम्मीद है कि अन्य कार्यो की तरह यह कार्य भी जल्दी ही प्रधानमंत्री मोदी करेंगे।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उन्नत बख्तरबंद वाहनों (ट्रैक्ड और व्हील्ड) का अनावरण किया

(जीएनएस)।

रक्षा विभाग (आरएंडडी) के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने 25 अप्रैल, 2026 को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर स्थित डीआरडीओ प्रयोगशाला परिसर में उन्नत बख्तरबंद वाहनों (ट्रैक्ड एवं व्हील्ड) का अनावरण किया। इन अत्याधुनिक वाहनों को व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (वीआरडीई) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। आधुनिक तकनीक से लैस ये बख्तरबंद वाहन सशस्त्र बलों की बदलती और जटिल परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।

दोनों उन्नत बख्तरबंद वाहनों को स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित 30 मिमी के क्रूलेस टरेट से सुसज्जित किया गया है, जो गतिशीलता, मारक क्षमता और सुरक्षा की आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इन वाहनों में हाई-पावर इंजन और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का समावेश किया गया है, जिससे उच्च पावर-टू-वेट अनुपात, बेहतर गति, तीव्र ढलानों एवं कठिन बाधाओं को पार करने की क्षमता सुनिश्चित होती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, इनमें चारों ओर मॉड्यूलर ब्लास्ट और बैलिस्टिक प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है, जो एसटीएएनएजी लेवल 4 तथा 5 के मानकों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, हाइड्रो जेट प्रणाली से युक्त यह एम्फीबियन प्लेटफॉर्म जल अवरोधों को पार करने में सक्षम है, जिससे इसकी ऑपरेशनल लचीलापन

और बहुउद्देशीय उपयोगिता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

30 मिमी का क्रू-लेस टरेट 7.62 मिमी पीकेटी गन के साथ एकीकृत है और इसे एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों के प्रक्षेपण के लिए भी कॉनफि गर किया गया है, जिससे इसकी मारक क्षमता व बहुआयामी उपयोगिता और बढ़ जाती है। इसके मूल डिजाइन में लचीलापन रखा गया है, जिससे इसे विभिन्न परिचालन भूमिकाओं के अनुरूप आसानी से कॉनफि गर किया जा सकता है। इन उन्नत बख्तरबंद वाहनों में स्वदेशी सामग्री की हिस्सेदारी वर्तमान में लगभग 65 प्रतिशत है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 90 प्रतिशत तक ले जाने की योजना है, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और सुदृढ़ करेगा।

इन वाहनों का निर्माण दो औद्योगिक साझेदारों टाटा एडवांस्ड सिस्टमस लिमिटेड और भारत फोर्ज लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिन्हें कई एमएसएमई का सहायता प्राप्त है। इस सहयोग के परिणामस्वरूप, विकसित हो रहे रक्षा इकोसिस्टम को मजबूती मिली है।

इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और आमार्मेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम्स (एसीई); प्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज इंटरैक्शन (पीसीएंडएसआई) के महानिदेशक; टीएएसएल पुणे के सीईओ व एमडी; बीएफएल पुणे के वाइस चेयरमैन तथा जॉइंट एमडी; एवं उद्योग जगत के अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के निदेशक और वैज्ञानिक भी उपस्थित थे, जिनमें व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, आमार्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी, हाई एनर्जी मैटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी, कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (इंजीनियर्स) शामिल हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में तापमान बढ़ने के मद्देनजर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने व्यापक लू संबंधी दिशानिर्देश जारी किए

उत्तर-पश्चिम, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत में लू चलने की संभावना: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने नागरिकों को एहतियाती उपाय अपनाने की सलाह दी है; विस्तृत दिशानिर्देश ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

(जीएनएस)।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारत मौसम विज्ञान विभाग ने लू की स्थिति को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश और सलाह जारी की है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और सामान्य से अधिक गर्मी की स्थिति बनी हुई है।

नवीनतम आकलन के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान वर्तमान में 40ट सेल्सियस से 44ट सेल्सियस के बीच है, जिसमें श्री गंगानगर (राजस्थान) में उच्चतम तापमान 44.5ट सेल्सियस दर्ज किया गया है। कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 5ट सेल्सियस या उससे अधिक देखा गया है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते तापीय तनाव की आशंका को दशार्ता है।

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य भारत के कुछ इलाकों में लू चलने की प्रबल संभावना है। साथ ही, तटीय और पूर्वी क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका है, जबकि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में रातें गर्म रहने की संभावना है, जिससे असुविधा और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और बढ़ सकते हैं।

विभाग ने आगे अनुमान लगाया है कि उत्तर-पश्चिमी भारत में अधिकतम तापमान में 27 अप्रैल तक कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, जिसके बाद धीरे-धीरे गिरावट आएगी , जबकि मध्य और अन्य क्षेत्रों में पूवार्नुमान अवधि के दौरान तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि और उसके बाद गिरावट देखी जा सकती है।

मौजूदा और पूवार्नुमानित परिस्थितियों को देखते हुए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने लू से बचाव के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं और नागरिकों को आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। इनमें सीधे धूप में लंबे समय तक रहने से बचना, विशेष रूप से दोपहर के चरम समय में, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, हल्के और हवादार कपड़े पहनना और उच्च तापमान के दौरान कठिन बाहरी गतिविधियों से बचना शामिल है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से ही किसी स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित व्यक्तियों जैसे संवेदनशील समूहों के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने इस बात पर जोर दिया है कि गर्मी से होने वाली बीमारियों जैसे कि हीट एग्जॉस्टशन और हीट स्ट्रोक को कम करने के लिए प्रारंभिक जागरूकता और निवारक उपाय महत्वपूर्ण हैं। आईएमडी के विस्तारित पूवार्नुमान के अनुसार, अगले 7 दिनों तक कई क्षेत्रों में , विशेष रूप से निम्नलिखित भागों में, लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है:

उत्तर पश्चिम भारत (पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश)

मध्य भारत (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ)

चयनित दक्षिणी क्षेत्र (केरल और माहे)

इसके अलावा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सहित तटीय राज्यों में गर्म और आर्द्र मौसम की स्थिति रहने की उम्मीद है, जबकि उत्तरी मैदानी इलाकों में रात में गर्मी का प्रकोप जारी रह सकता है, जिससे रात के समय लू लगने की समस्या और बढ़ जाएगी।

आईएमडी के अप्रैल से जून 2026 के मौसमी पूवार्नुमान के अनुसार , पूर्वी, मध्य और उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों और दक्षिण-पूर्वी प्रायद्वीप में सामान्य से अधिक लू चलने की संभावना है, जो मौजूदा गर्म मौसम के दौरान निरंतर तैयारी और शमन उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

आईएमडी ने लू से बचाव के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं , जिनमें क्या करें और क्या न करें, तैयारी के उपाय और क्षेत्र-विशिष्ट सलाह शामिल हैं। ये दिशानिर्देश आम जनता के लिए https://mausam.imd.gov.in/responsive/heatwave_guidance.php पर उपलब्ध हैं । इन दिशानिदेर्शों का उद्देश्य व्यक्तियों, समुदायों और स्थानीय प्रशासनों को स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने और अत्यधिक गर्मी की स्थितियों से निपटने की क्षमता बढ़ाने में सहायता करना है।

मौसम विज्ञान विभाग तापमान के रुझानों पर लगातार नजर रख रहा है और समय पर पूवार्नुमान एवं चेतावनी जारी कर रहा है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम जानकारी प्राप्त करते रहें और निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन करें।

गर्मी के मौसम में खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी

(जीएनएस)। गर्मी के मौसम में खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो तेज धूप में बाहर निकलते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में भी स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम से लेकर जगह-जगह वॉटरकूलर लगाकर पीने के पानी का इंतजाम किया गया है।

लखनऊ (ब्यूरो)। गर्मी के मौसम में खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो तेज धूप में बाहर निकलते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में भी स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम से लेकर जगह-जगह वॉटरकूलर लगाकर पीने के पानी का इंतजाम किया गया है। पर इन वॉटरकूलर्स का पानी स्टूडेंट्स के लिए कितना सेफ है, इसकी जांच भी जरूरी है। दरअसल, एलयू के कई स्टूडेंट्स का कहना है कि कैंपस में हाई टीडीएस वाले पानी की सप्लाई के चलते उन्हें कई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने का खतरा बना रहता है। इसकी हकीकत जानने के लिए दैनिक जागरण आईनेक्स्ट ने खुद इन वॉटरकूलर्स से सप्लाई किए जा रहे पीने के पानी का टीडीएस चेक किया। क्या कुछ रहा रिजल्ट, जानिए इस रिपोर्ट में

1- स्थान- जियोलॉजी डिपार्टमेंट के सामने

जियोलॉजी डिपार्टमेंट के सामने लगे वॉटर कूलर से जियोलॉजी डिपार्टमेंट, मैथ्स डिपार्टमेंट, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, जूलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स पानी पीते हैं। पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए जब टीडीएस मीटर से पानी का टीडीएस चेक किया गया तो ये 551 निकला, जो आदर्श मानक के मुताबिक ज्यादा है।

2- स्थान- सोशल वर्क डिपार्टमेंट के सामने

समय- दोपहर 1.35 बजे

सोशल वर्क डिपार्टमेंट के सामने, साइबर लाइब्रेरी में पूरे कैंपस के बच्चे आते हैं और फिर ओएनजीसी बिल्डिंग के स्टूडेंट्स भी पानी पीने के लिए इधर ही आते हैं। यहां के पानी का टीडीएस 518 निकला। यहां मौजूद स्टूडेंट्स का कहना था कि कई बार पानी पीने के बाद उनको गले में खराश की प्रॉब्लम हो जाती है।

3- स्थान- आट्र्स फैकल्टी

समय- दोपहर 2.50 बजे

आट्र्स फैकल्टी में सेकेंड फ्लोर पर लगे वॉटर कूलर से कई डिपार्टमेंट्स जैसे एआईएच, एमआईएच, हिंदी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स पानी पीने आते हैं, यहां का टीडीएस चेक करने पर सबसे ज्यादा 609 निकला। जो मानक से काफी ज्यादा है।

यहां भी ध्यान की जरूरत

477 यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रसंघ भवन के सामने लगे वॉटरकूलर का टीडीएस

440 कॉमर्स फैकल्टी के सामने लगे वॉटरकूलर का टीडीएस

438 गेट नं। 4 के पास लगे वॉटरकूलर का टीडीएस

442 गेट नं। 3 के पास लगे वॉटरकूलर का टीडीएस

453 गेट नं। 1 के पास लगे वॉटरकूलर का टीडीएस

क्या हैं बीएसआई के मानक

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडड्र्स के मानकों के मुताबिक, 300 तक का टीडीएस अच्छा माना जाता है जबकि 300-500 का टीडीएस एक्सेप्टेबल माना जाता है, लेकिन अगर टीडीएस 500 से ज्यादा है तो फिर ध्यान देने की जरूरत है। इसे हाई टीडीएस की कैटेगरी में रखा जाता है। हाई टीडीएस को लेकर केजीएमयू के मेडिसिन डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट डॉ। डी हिमांशू का कहना है कि 500 के ऊपर का टीडीएस स्टूडेंट्स को ओबेसिटी और डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। हालांकि, ये इस पर निर्भर करता है कि पानी में किन तत्वों की मात्रा ज्यादा है।

गरीबी में जिया 'कालू' कैसे बना पीएम मोदी का 'सेलिब्रिटी' सारथी! नाव से गंगा की सैर कराते ही बदल गई जिंदगी, लोग नहीं कर पा रहे यकीन

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के एक बेहद साधारण नाविक गौरांग विश्वास, जिन्हें गांव में लोग 'कालू' के नाम से पुकारते हैं, उनकी किस्मत ने ऐसी करवट ली कि वह रातों-रात पूरे देश की सुर्खियों में आ गए. कोलकाता के प्रिंसेप घाट पर अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरांग की नाव पर सवारी की, जिससे यह गरीब परिवार और उनका पूरा गांव गोपालपुर अचंभित है. 15 साल पहले मछली कम होने और गरीबी के कारण रोजी-रोटी की तलाश में अपना गांव छोड़ने वाले गौरांग आज एक 'सेलिब्रिटी' बन चुके हैं. जानें पूरी कहानी.

पश्चिम बंगाल की सरगर्मी भरी राजनीति के बीच अक्सर बड़े-बड़े उलटफेर देखने को मिलते हैं, लेकिन हुगली के एक छोटे से गांव गोपालपुर के रहने वाले 70 वर्षीय गौरांग विश्वास (कालू) के लिए बीता शुक्रवार किसी सपने के सच होने जैसा था. कोलकाता के ऐतिहासिक प्रिंसेप घाट पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक उनकी नाव पर सवार हुए, तो गौरांग के हाथ पतवार थामे थोड़े ठिठक जरूर गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक असीम संतोष था. ुल्लॅ'.ल्लीद२१8ू्ह्ण में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी ने न केवल उनकी नाव पर गंगा विहार किया, बल्कि इस मुलाकात ने गौरांग के साधारण से जीवन को एक नई पहचान दे दी है. वह नाविक जो कभी पेट पालने के लिए गंगा में मछलियां

पकड़ता था और तंगहाली के कारण दर-दर भटकने को मजबूर था, आज देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति का 'सारथी' बनकर चर्चा में है. प्रधानमंत्री की इस सादगी भरी मुलाकात ने गौरांग के पूरे परिवार को रातों-रात सेलिब्रिटी बना दिया है.

प्रिंसेप घाट का वो पल जब पीएम मोदी अचानक पहुंचे पास

कोलकाता के प्रिंसेप घाट पर रोजाना की तरह नाविकों की कतार लगी थी. गौरांग विश्वास भी अपनी नाव लेकर सवारियों के इंतजार में खड़े थे. रिपोर्ट के अनुसार, सुबह एक अजनबी शख्स आया और उसने सात नावें बुक कीं. गौरांग को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि इन नावों में कौन बैठने वाला है. तभी उन्होंने देखा कि सफेद कुर्ता, कंधे पर हल्का सा चौरस और हाथ में कैमरा लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी नाव की ओर बढ़ रहे हैं. यह नजारा देख गौरांग की आंखें फटी की फटी रह गईं. जिसे उन्होंने सिर्फ टीवी पर देखा था, वह साक्षात उनके सामने खड़ा था और उनकी ही नाव पर पैर रख रहा था.

जब बेटे को लगा कि पिता किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए

शुरूआत में जब गौरांग के बेटे शंकर के पास रिश्तेदारों और अनजान लोगों के फोन आने शुरू हुए, तो परिवार बुरी तरह घबरा गया. उन्हें लगा कि शायद कोई अनहोनी हो गई है. शंकर ने मीडिया को बताया कि जब उन्होंने घबराहट में अपने पिता को फोन किया, तो गौरांग ने बहुत संक्षिप्त जवाब दिया. उन्होंने बस इतना कहा, 'मैं अभी बहुत व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं.' उस वक्त परिवार को अंदाजा नहीं था कि उनके पिता देश के प्रधानमंत्री को गंगा की लहरों की सैर करा रहे हैं. बाद में जब टीवी पर फुटेज चली और सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुए, तब जाकर परिवार की जान में जान आई और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

गौरांग विश्वास का जीवन संघर्षों की एक लंबी दास्तान है. करीब 15 साल पहले वह हुगली के बलॉगढ़ में गंगा में मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे. लेकिन वक्त बदला और गंगा में मछलियां कम होने लगीं, जिससे परिवार का पेट पालना दूभर हो गया. तभी उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और अपना गांव छोड़कर कोलकाता के प्रिंसेप घाट पर आकर नाव चलाने लगे. आपको जानकर हैरानी होगी कि गौरांग की अपनी कोई नाव नहीं है.

डीपीआईआईटी ने ₹10,000 करोड़ के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 में पूंजी परिनियोजन के प्रवाह को सुव्यवस्थित करने हेतु परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए

डीपीआईआईटी ने ₹10,000 करोड़ के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 में पूंजी परिनियोजन के प्रवाह को सुव्यवस्थित करने हेतु परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए

स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0 को सेबी की ओर से पंजीकृत एआईएफ के जरिए लागू किया जाएगा, जिससे निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके और स्टार्टअप फंडिंग तक पहुंच का विस्तार किया जा सके

स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0 के कार्यान्वयन का नेतृत्व सिडबी करेगा; डीपीआईआईटी अपनी पहुंच और क्षमता के विस्तार के लिए अतिरिक्त एजेंसी को शामिल करेगा

स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0 उत्प्रेरक कोष के तौर पर कार्य करेगा, निजी पूंजी जुटाने को अनिवार्य बनाएगा और इकोसिस्टम के विकास में सहयोग करेगा

(जीएनएस)।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (एफओएफ 2.0) के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश 10,000 करोड़ रुपये के कोष का परिचालन करने के लिए एक संरचित फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं, जिसमें कोष के इस्तेमाल, संचालन और निगरानी के लिए स्पष्ट तौर पर परिभाषित तंत्र शामिल हैं। इसका उद्देश्य भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में पूंजी के प्रवाह की दक्षता में सुधार करना है।

यह योजना सेबी में पंजीकृत श्रेणियों क और क्क के वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) के प्रति प्रतिबद्धताओं के माध्यम से लागू की जाएगी, जो डीपीआईआईटी की ओर से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में निवेश करेंगे। ऐसा करने से पूंजी आवंटन में अनुशासन, निजी निवेशों को आकर्षित करने और कई क्षेत्रों, चरणों और भौगोलिक क्षेत्रों में वित्तपोषण की व्यापक पहुंच के सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) प्रारंभिक कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर काम करेगा और एक सुव्यवस्थित एआईएफ चयन और निगरानी प्रक्रिया के जरिए क्रियान्वयन करेगा। डीपीआईआईटी पहुंच बढ़ाने, क्षेत्रीय विशेषज्ञता को बेहतर करने और ऐसी योजनाओं के प्रबंधन के लिए संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करने के लिए अतिरिक्त कार्यान्वयन एजेंसी को भी शामिल करेगा।

इकोसिस्टम में मौजूद विशेष कमियों को दूर करने के लिए, परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों में एआईएफ (वैकल्पिक पूंजी निवेश) का संरचनात्मक तौर पर बंटवारा किया गया है, जिसमें गहन प्रौद्योगिकी-केंद्रित कोष, शुरूआती विकास वाले स्टार्टअप को सहयोग देने वाले माइक्रो वेंचर कैपिटल फंड, नवोन्मेषी और प्रौद्योगिकी-आधारित विनिर्माण क्षेत्रों पर केंद्रित कोष और क्षेत्र और चरण-संबंधी फंड शामिल हैं। प्रत्येक खंड के लिए निर्धारित मापदंड हैं, जिनमें कोष सीमा, सरकारी योगदान सीमा, कार्यकाल और न्यूनतम निजी पूंजी जुटाने का अनुपात शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बाजार अनुशासन बनाए रखते हुए पूंजी को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निर्देशित किया जाए।

दिशा-निदेर्शों में एआईएफ के लिए दो-चरणीय चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कार्यान्वयन एजेंसी प्रारंभिक जांच-पड़ताल करेगी, जिसके बाद वेंचर कैपिटल निवेश समिति की ओर से मूल्यांकन किया जाएगा। यह समिति टीम के ट्रैक रिकॉर्ड, कोष प्रबंधन की क्षमता और निवेश रणनीति के आधार पर प्रस्तावों का आकलन करेगी। समिति में उद्योग, शिक्षा जगत और नवाचार इकोसिस्टम के प्रतिष्ठित नेतृत्वकर्ता शामिल हैं, जिनमें वल्लभ भंसाली, डॉ. अशोक झुनझुनवाला, डॉ. रेणु स्वरूप, डॉ. चिंतन वैष्णव और राजेश गोपीनाथन शामिल हैं। इनके साथ ही, कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, जो डीप टेक, मैन्युफैक्चरिंग, नीति और वेंचर इकोसिस्टम में विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0 को प्रत्यक्ष निवेशक के बजाय उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करने के लिए विकिसत किया गया है, जिससे निजी पूंजी भागीदारी के माध्यम से कई गुना असर हो सके। दिशानिदेर्शों में न्यूनतम निजी पूंजी जुटाने को अनिवार्य किया गया है।

'टीएमसी के गुंडे अपने लिए नया काम-धंधा तलाशने लगे', बंगाल में सीएम योगी की हुंकार

कोलकाता। (जीएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीएमसी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में सत्तारूढ़ दल जो गुंडे अब तक दादागिरी करते थे उन्हें हार का अंदाजा हो गया है।

टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए नया काम-धंधा तलाशने लगे हैं। कोई सोच रहा है कि कहां पंचर की दुकान लगाऊं तो कोई सड़क पर झाड़ू लगाने की तैयारी कर रहा है।

बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले नदिया जिले के नवद्वीप में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने दो टूक चेतावनी दी। कहा कि चार मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो इन गुंडों को बंगाल में छिपने के लिए जगह तक नहीं मिलेगी।

सीएम योगी ने चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान नवद्वीप की आध्यात्मिक पहचान व सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित करते हुए कहा कि जिस भूमि ने दुनिया को भक्ति और वैष्णव परंपरा का संदेश दिया, जो बंगाल कभी भारत को पहचान देती थी आज वही राज्य टीएमसी के शासन में अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा है।

सीएए के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा कि दीदी इसका विरोध सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है। दीदी को चिंता सता रही है कि अगर हिंदू अधिक हो गए तो सड़कों पर इफ्तारी कैसे होगी?

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव में हर भारतीय का दांव लगा है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए न केवल राज्य में जनसांख्यिकीय बदलाव ला रहे हैं, बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी फैल रहे हैं। यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री ने सेबी के 38वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य भाषण दिया

श्रीमती सीतारमण ने उभरती वैश्विक चुनौतियों के लिए सेबी और सभी विनियमित संस्थाओं को साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के प्रति आगाह किया

सेबी को हर प्रमुख मंच पर क्षेत्रीय भाषाओं में जन-जागरूकता पर बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहिए: केंद्रीय वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री ने सेबी की देशव्यापी निवेशक जागरूकता पहल 'मिशन जागरूक' का भी शुभारंभ किया

वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने बिना पंजीकृत 'फिन-फ्लुएंसर्स' के खिलाफ सेबी की कार्रवाई की तारीफ की, जिम्मेदार वित्तीय शिक्षा के लिए सक्षम ढांचे का आ'ान किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज मुंबई में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के 38वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भाषण दिया।

इस अवसर पर श्रीमती सीतारमण ने सेबी की देशव्यापी निवेशक जागरूकता पहल 'मिशन जागरूक' का डिजिटल रूप से शुभारंभ भी किया।

अपने मुख्य वक्तव्य में केंद्रीय वित्त मंत्री ने सेबी से उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि किसी बड़े एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, क्लियरिंग कॉरपोरेशन या बड़े ब्रोकर पर एक सफल साइबर हमला राष्ट्रीय स्तर पर बाजारों को बाधित कर सकता है, संपत्ति नष्ट कर सकता है और जनविश्वास को हिला सकता है, जिसे फिर से स्थापित करने में वर्षों लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि एआई आधारित उपकरण साइबर हमलों को तेज, अधिक अनुकूलनीय, व्यापक और कई मामलों में अधिक स्वायत्त बना रहे हैं। ये जोखिम कई रूपों में सामने आ सकते हैं,जैसे- सिस्टम की कमजोरियों की स्वचालित पहचान,

सोर्स कोड में दुर्भावनापूर्ण हस्तक्षेप, सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन पर हमले और ऐसे समन्वित हमले जो पहचान से बचने के लिए वास्तविक समय में बदलते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'इसलिए केवल सेबी ही नहीं, बल्कि सभी विनियमित संस्थाओं को अत्यधिक सतर्क रहना होगा। हमले के उपकरण तेजी से विकसित हो रहे हैं और बचाव के उपकरणों को उससे भी तेज विकसित होना होगा।'

वित्त मंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग के साथ सोशल मीडिया पर नकली निवेश वीडियो और ऐप्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिनमें से कई 'डीपफेक एआई' का उपयोग कर नेताओं की नकली पहचान प्रस्तुत करते हैं

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अप्रैल 2025 से लागू सेबी का साइबर सुरक्षा और साइबर रेजिलिएंस फ्रेमवर्क सराहनीय है और इस पर आगे और काम किया जा सकता है।

वित्त मंत्री ने बताया कि सेबी की डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला उन्नत विश्लेषण और एआई/एमएल मॉडल का उपयोग कर जटिल बाजार हेरफेर पैटर्न और नेटवर्क आधारित धोखाधड़ी का पता लगा रही है। उन्होंने 'सेबी चेक' पहल की भी सराहना की, जो निवेशकों को धन हस्तांतरण से पहले पंजीकृत मध्यस्थों के भुगतान विवरण की जांच करने की सुविधा देती है। उन्होंने कहा कि इन पहलों का विस्तार तेजी और व्यापकता के साथ किया जाना चाहिए तथा क्षेत्रीय भाषाओं में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, साथ ही फर्जी सामग्री के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि 'सॉफ्ट-टच' नियमन और सार्वजनिक परामर्श आर्थिक दक्षता और प्रभावी शासन के लिए आवश्यक हैं। अत्यधिक विस्तृत नियम पुस्तिका के बजाय सिद्धांत-आधारित विनियमन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2023 में नियामक प्रक्रिया में सार्वजनिक परामर्श को शामिल करने की बात कही गई थी।वित्त मंत्री ने सेबी द्वारा परामर्शात्मक दृष्टिकोण अपनाने, जनमत आमंत्रित करने और बाजार प्रतिभागियों से संवाद करने की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारे निवेशक वैश्विक हैं और नियामकीय विकास का प्रभाव सीमाओं से परे जाता है, इसलिए नियामकीय संवाद केवल घरेलू स्तर तक सीमित नहीं रह सकते। श्रीमती सीतारमण ने शिकायत निवारण तंत्र को विश्वसनीय, सुलभ और समयबद्ध बनाए रखने पर भी जोर दिया।

उन्होंने बिना पंजीकृत 'फिन-फ्लुएंसर्स' के खिलाफ सेबी की कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा कि जिम्मेदार वित्तीय शिक्षा के लिए सक्षम ढांचे जरूरी हैं, लेकिन अनभिज्ञ खुदरा निवेशकों के भरोसे का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सेबी, आईईपीएफए और बाजार संस्थानों के साथ मिलकर कई 'निवेशक शिविर' कार्यक्रम आयोजित कर चुका है, जिससे अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्तियों को कम करने और जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली है।

उन्होंने सेबी से भारतीय प्रतिभूति बाजार में समान केवाईसी मानदंड लागू करने और प्रक्रियाओं के सरलीकरण व डिजिटलीकरण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "सेबी के पास इस क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए निवेशकों की भागीदारी का पैमाना, डिजिटल बुनियादी ढांचे की गहराई और साथी नियामकों के बीच संस्थागत विश्वसनीयता है।"

सेबी के अध्यक्ष श्री तुहिन कांत पांडे ने कहा कि विगत वर्षों के दौरान सेबी ने स्क्रीन-आधारित ट्रेडिंग, डीमैटेरियलाइजेशन, रोलिंग सेटलमेंट, कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने और जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित करने जैसे कई बुनियादी सुधार किए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत में 5,900 से अधिक सूचीबद्ध कंपनियां और 14 करोड़ से अधिक निवेशक हैं। पिछले दशक में बाजार पूंजीकरण में लगभग 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है, जबकि म्यूचुअल फंड संपत्तियों में 20 प्रतिशत से अधिक की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सेबी ने पिछले एक वर्ष में सभी हितधारकों के साथ मिलकर व्यापार सुगमता के लिए व्यापक सुधार किए हैं, जिनका उद्देश्य नियमों को सरल बनाना, अस्पष्टताओं को दूर करना और पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना है।

विश्वास, सेवा और राष्ट्र निर्माण के 56 वर्ष

भारत के शहरी भविष्य को संवारने के 56 वर्ष का उत्सव

(जीएनएस)।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत भारत की अग्रणी टेक्नो-फाइनेंसिंग नवरत्न सीपीएसई, आवासन एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) ने आज अपना 56वां स्थापना दिवस "संकल्प दिवस" के रूप में मनाया। इस समारोह में पिछले साढ़े पांच दशकों में हुडको की शानदार उपलब्धियों को उजागर किया गया। इस समारोह में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल, आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री टोखन साहू, मंत्रालय के सचिव श्री श्रीनिवास कटिकिथाला (आईएएस), और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

उद्घाटन समारोह के बाद 'शहरी चुनौती कोष (यूसीएफ)' और 'शहरी निवेश विंडो (व्रहक्ठ)' पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें व्रहक्ठ तकनीकी सहायता फ्रेमवर्क का अनावरण किया गया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य इन योजनाओं और शहरी परिदृश्य को बदलने की उनकी क्षमता के बारे में जानकारी प्रसारित करना था। इस सत्र में विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों, कई नगर आयुक्तों और हुडको के कर्मचारियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर संबोधन में श्री मनोहर लाल ने राष्ट्र के बुनियादी ढांचे के विकास में हुडको के महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण के अनुरूप, हुडको भारत सरकार की शहरी परिवर्तन की नई योजनाओं के माध्यम से सामने आने वाले विशाल अवसरों का लाभ उठाने में अपनी नई पेशकश व्रहक्ठ के जरिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इन योजनाओं में 'शहरी चुनौती कोष (यूसीएफ)' भी शामिल है।

श्री टोखन साहू ने पीएमएवाई सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को दिए गए समर्थन और राष्ट्र के शहरी परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हुडको की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत में शहरीकरण की गति बहुत तेज है। अनुमान है कि 2050 तक 50% से अधिक आबादी शहरों में निवास करेगी, जिसके लिए शहरी बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में, उन्होंने परिवर्तनकारी 'अर्बन चैलेंज फंड' (व१ुंल्ल उँ''ील्लॅं ॠक्ष्ल्ला) की शुरूआत को गेम-चेंजिंग पहल बताया। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 'व्रहक्ठ' के माध्यम से, शहरी परिवर्तन का नया अध्याय लिखा जाएगा; इसके तहत शहरी स्थानीय निकायों को ऐसी परियोजनाओं की पहचान करने में सक्षम बनाया जाएगा, जो बैंक से वित्तपोषण प्राप्त करने योग्य हों और जिनसे राजस्व उत्पन्न करने वाला ऐसा बुनियादी ढांचा विकसित किया जा सके, जिसकी वित्तीय व्यवहार्यता सिद्ध हो चुकी हो।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने कहा कि हुडको में मौलिक परिवर्तन आया है और इसने अपने लिए विशिष्ट स्थान बनाया है; इसे प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में पहचान मिली है, जो विशेष रूप से यूसीएफ और व्रहक्ठ की शुरूआत के साथ शहरी क्षेत्र में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। कंपनी की पिछली उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हुडको 'विकसित भारत' की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि सतत शहरी विकास में योगदान देने के लिए हुडको की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर हुडको के मुख्य महा प्रबंधक (सीएमडी) ने सभा को बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में हुडको ने अब तक का सबसे अधिक, लगभग 1,65,000 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है और लगभग 52,000 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े पाँच दशकों से, हुडको ने लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपने तीन मुख्य स्तंभों - वित्तपोषण, परामर्श और क्षमता निर्माण - के माध्यम से पूरे देश में सतत आवास का विकास किया है। हुडको, 'विकसित भारत 2047' के विजन के अनुरूप, अधिक मजबूत, स्मार्ट और समावेशी भारत के निर्माण के लिए नई प्रतिबद्धता के साथ पूरी तरह तैयार है।

स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, कई आंतरिक प्रकाशनों का विमोचन किया गया। इस अवसर पर हुडको के कर्मचारियों की लंबी एवं सराहनीय सेवा के लिए उन्हें, तथा विभिन्न राज्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रमुख हितधारकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक संध्या के साथ हुआ, जिसमें हमारे देश की समृद्ध शास्त्रीय परंपराओं को अत्यंत सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया गया।

सहालग के चलते लखनऊ में बढ़ी कॉमर्शियल सिलिंडर की डिमांड, 20-25 दिन तक की वेटिंग

सहालग के सीजन में शादी-विवाह और अन्य आयोजनों के बीच कॉमर्शियल गैस सिलिंडर की किल्लत के लोगों को लंबी वेंटिंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि कॉमर्शियल सिलिंडर की क्राइसिस की वजह से मेस संचालकों और स्ट्रीट वेंडर्स को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

लखनऊ, (जीएनएस)। सहालग के सीजन में शादी-विवाह और अन्य आयोजनों के बीच कॉमर्शियल गैस सिलिंडर की किल्लत के लोगों को लंबी वेंटिंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि कॉमर्शियल सिलिंडर की क्राइसिस की वजह से मेस संचालकों और स्ट्रीट वेंडर्स को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एलपीजी सप्लाई में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी डिलीवरी में चार से पांच दिन लग रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से सभी गैस एजेंसियों से डिमांड और सप्लाई की रिपोर्ट तलब की गई है ताकि यह पता चल सके कि आखिर समस्या कहां पर है।

कॉमर्शियल सिलिंडर की डिमांड की बात की जाए तो यह हर दिन के हिसाब से अलग-अलग है। कभी दिन में 10 हजार से अधिक सिलिंडर की डिमांड है तो सहालग तेज होने पर ये आंकड़ा 16 से 17 हजार तक पहुंच रहा है। ऐसे में, शादी या अन्य समारोह के लिए सिलिंडर से जुड़े जो आवेदन आ रहे हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से स्क्रूटनी की जा रही है। जिससे डिमांड और सप्लाई में बहुत अधिक गैप न आ सके। सभी गैस एजेंसियों को पहले ही निर्देश दिए जा रहे हैं कि जिस दिन सहालग तेज है, उस दिन कॉमर्शियल सिलिंडर का स्टॉक पर्याप्त रखें, ताकि उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत के हिसाब से सिलिंडर मिल सके।

राजधानी में गोमतीनगर, जानकीपुरम में जो बड़ी गैस एजेंसियां हैं, जिनके उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है, उन्हें एलपीजी सिलिंडर की डिलीवरी के लिए वेट करना पड़ रहा है। इन एजेंसियों से जुड़े उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलिंडर की बुकिंग के लिए चार से पांच दिन इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं, जिन गैस एजेंसियों के उपभोक्ता कम हैं, उनके यहां एक से डेढ़ दिन में ही सिलिंडर डिलीवर हो रहा है।

अगले महीने से राजधानी में बड़ा मंगल शुरू होने जा रहा है। इस बार यह आयोजन दो महीने चलेगा। शहर में 150 से अधिक प्वाइंट्स पर बड़े भंडारे लगेंगे, जिनमें कॉमर्शियल सिलिंडर का यूज होगा अभी से ही कई आयोजकों की ओर से सिलिंडर के लिए आवेदन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

छोटे स्ट्रीट वेंडर्स भी परेशान

हजरतगंज, गोमतीनगर, इंदिरानगर के स्ट्रीट फूड वेंडर्स का कहना है कि उन्हें भी कॉमर्शियल सिलिंडर समय से नहीं मिल पा रहा है। कई बार तो उन्हें 20 से 25 दिन की वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से न चाहते हुए भी उन्हें अपनी दुकान चलाने के लिए घरेलू एलपीजी सिलिंडर का सहारा लेना पड़ रहा है।

इस तरह समझें

30 लाख से अधिक एलपीजी कंज्यूमर्स शहर में, 3 गुना तक बढ़ गई है कॉमर्शियल सिलिंडर की डिमांड

15 हजार प्रति दिन कॉमर्शियल सिलिंडर की डिमांड सामने आ रही

18 हजार प्रति सिलिंडर डिमांड पहुंचती सहालग तेज होने पर

82 हजार ही पीएनजी कनेक्शनधारक शहर में, 10 हजार से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स भी यूज करते कॉमर्शियल सिलिंडर

बोले लोग

कॉमर्शियल सिलिंडर के लिए अच्छी खासी वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। हमें तो 20 से 25 दिन बाद ही सिलिंडर मिल रहा है। इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। - हर्षवर्धन, मेस संचालक, हजरतगंज

कॉमर्शियल सिलिंडर टाइम से न मिलने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो तीन से चार दिन में मिल जाता था, लेकिन अब दो दो सप्ताह इंतजार करना पड़ता है। - अजय, जियामऊ

पहले तो घरेलू एलपीजी सिलिंडर एक से दो दिन में ही घर आ जाता था, लेकिन अब तो चार से पांच दिन इंतजार करना पड़ता है। समय से सिलिंडर न मिलने से दिक्कत होती है। - मनु कश्यप, गोमतीनगर

सहालग की वजह से कॉमर्शियल सिलिंडर की मांग में दो से तीन गुना तक बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। इसके लिए सभी एजेंसियों को पहले ही डिमांड के अनुसार स्टॉक रखने को कहा गया है। वहीं, जो बड़ी गैस एजेंसियां हैं, जिनके कंज्यूमर्स अधिक हैं, वहां एलपीजी डिलीवरी में चार से पांच दिन का समय लग रहा है। इस पर काम किया जा रहा है। - ज्योति गौतम, एडीएम, सिविल सप्लाई

लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, 30 बीघा में विकसित कॉलोनियां ध्वस्त, 4 निर्माण सील

राजधानी लखनऊ में लगातार अवैध प्लॉटिंग पर एलडीए की ओर से कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को गोमती नगर, चिनहट, बीबीडी और सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्रों में अभियान चलाया गया है।

लखनऊः (जीएनएस)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने गोसाईंगंज क्षेत्र में बड़ा अभियान चलाया। एलडीए की टीम ने गोसाईंगंज में लगभग 30 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही दो अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर

चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया है।

प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि महेंद्र शुक्ला और अन्य द्वारा ग्राम लक्ष्मनपुरवा व दुलारमऊ में करीब 20 बीघा में अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। वहीं, दुर्गेश सोनी और अन्य द्वारा सुल्तानपुर रोड स्थित ग्राम बक्कास में लगभग 10 बीघा क्षेत्र में बिना स्वीकृति प्लॉटिंग की जा रही थी। इन दोनों मामलों में एलडीए से ले-आउट स्वीकृत नहीं कराया गया था, जिसके चलते कार्रवाई की गई है।

सुशांत गोल्फ सिटी में चलाया गया अभियान

इसके अलावा गोमती नगर, चिनहट, बीबीडी और सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्रों में भी अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रहलाद सिंह, विकास सिंह, डॉ. विक्रांत सिंह, रईस हैदर और मोहम्मद इरफान समेत अन्य द्वारा किए जा रहे चार अवैध व्यावसायिक निमार्णों को सील कर दिया गया। एलडीए ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृति प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

जनगणना ड्यूटी और एफआईआर का खौफ... लखनऊ डीएम ने सख्त आदेश किया जारी

लखनऊ में जनगणना प्रशिक्षण से 694 प्रगणक और सुपरवाइजर अनुपस्थित पाए गए, जिसके बाद जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

लखनऊ में जनगणना प्रशिक्षण से 694 कर्मी अनुपस्थित। जिलाधिकारी ने गैरहाजिर कर्मचारियों को एफआईआर की चेतावनी दी। अनुपस्थिति पर कारण बताओ नोटिस, फिर निलंबन और एफआईआर।

लखनऊ। (जीएनएस)। जनगणना प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले प्रगणक और सुपरवाइजर के खिलाफ जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। बिना किसी कारण अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों को एफआइआर की चेतावनी दी गई है। 21 अप्रैल 2026 से लखनऊ में जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। यह प्रशिक्षण नगर निगम के विभिन्न जोनों में आयोजित किया जा रहा है।

जोन-1 में अमीनाबाद इंटर कालेज, जोन-2 में ऐशबाग ईदगाह, जोन-3 में केंद्रीय विद्यालय सेक्टर-जे कालेज इंदिरा नगर में प्रशिक्षण चल रहा है। 25 अप्रैल को हुए प्रशिक्षण के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए।

पहले चरण में अनुपस्थित कर्मियों

अलीगंज, जोन-4 में माडर्न एकेडमी विराम खंड-5 और लखनऊ पब्लिक स्कूल विराट खंड-4, जोन-5 में मानस नगर स्थित इंडिया लिटरेसी बोर्ड तथा जोन-7 में इरम पब्लिक कालेज और सेंट डोमिनिक सेवियो को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सेवा नियमों के तहत निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। लगातार अनुपस्थिति या ड्यूटी से इनकार करने पर धारा 11 के तहत एफआईआर दर्ज

'यूपी चुनाव में हमें 25 सीटें दे भाजपा, वरना अकेले लड़ेंगे', रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने लखनऊ पहुंचकर उठाई मांग

केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने मांग उठाई है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें गठबंधन के तहत 25 सीटें दे।

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। एनडीए के सहयोगी दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा है कि वह 2027 में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रामदास अठावले ने कहा कि उनकी पहली कोशिश यही है कि यूपी में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन, चुनाव लड़ने के लिए अगर उनकी 25 सीटों की मांग नहीं मानी जाती, तो फिर उनकी पार्टी अकेले ही मैदान में उतरेगी।

रामदास अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए की सहयोगी है और इसीलिए गठबंधन के तहत यूपी के चुनाव मैदान में उतरने की हमारी तैयारी है। उनकी मांग है कि गठबंधन में यूपी की 25 सीटें हमारी पार्टी रिपब्लिकन ऑफ इंडिया को दी जाएं। अगर हमारी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा तो पार्टी अपने दम पर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही अठावले ने मांग उठाई कि गांवों में दलित परिवारों को पांच-पांच एकड़ जमीन दी जाए और उनके लिए सामुदायिक केंद्र बनाएं जाएं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामदास अठावले ने कहा, 'उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद गुंडाराज खत्म हो गया है। साथ ही राम मंदिर का वर्षों पुराना मुद्दा भी सुलझ गया है। अब सीएम योगी से हमारी बस एक मांग है कि दलित परिवारों को रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन ना करना पड़े, इसलिए हर परिवार को गांव में ही पांच एकड़ जमीन दी जाए। सरकार के इस कदम से पलायन रुकेगा और दलित परिवार गरीबी से बाहर निकलेंगे। हम आज सीएम योगी से मुलाकात करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि प्रदेश में हमारी पार्टी आरपीआई को भी साथ लेकर चलें।'

बिहार और तमिलनाडु में भी उतारे प्रत्याशी

आपको बता दें कि मुख्य तौर पर महाराष्ट्र से आने वाली रामदास अठावले की आरपीआई ने हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में तीन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसके अलावा तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में आरपीआई 18 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इससे पहले 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आरपीआई ने 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिल पाई।

रामदास अठावले इस समय राज्यसभा के सांसद हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। हालांकि, लोकसभा या महाराष्ट्र की विधानसभा में उनकी पार्टी का कोई सदस्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगले साल, 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल करते हुए यूपी की 403 सीटों में से 255 अपने नाम की थी। वहीं, समाजवादी पार्टी को 111 सीटों पर जीत मिली थी।

लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनाव, जीएन शुक्ला 'चच्चू' अध्यक्ष और जितेंद्र यादव 'जीतू' महामंत्री निर्वाचित

(जीएनएस)।

लखनऊ। लखनऊ बार एसोसिएशन चुनाव के तीन पद का परिणाम शनिवार को आ गया है। पहले तीन पद के परिणाम की घोषणा की गई है। अध्यक्ष, महामंत्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का परिणाम आ गया है।

जीएन शुक्ला 'चच्चू' अध्यक्ष चुने गए हैं। महामंत्री पद पर जितेंद्र सिंह यादव उर्फ 'जीतू' ने जीत हासिल की है। मनीष श्रीवास्तव वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शुक्रवार को हुई शुरूआती गिनती में अध्यक्ष और महामंत्री पद पर कड़ा मुकाबला नजर आया, जिसमें जीएन शुक्ला 'चच्चू' और जितेंद्र यादव 'जीतू' ने बढ़त बना ली थी। अध्यक्ष पद पर जीएन शुक्ला के बाद सुरेश पांडेय थे। राजेंद्र शर्मा व परशुराम मिश्र भी प्रत्याशी थे।

महामंत्री पद पर जितेंद्र यादव ने मजबूत बढ़त बना ली थी। उनके बाद आदर्श मिश्रा, कुलदीप वर्मा, मारुत शर्मा व कामिनी ओझा थे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मुकाबला दिलचस्प व रोचक मुकाबला देखने को मिला। मनीष श्रीवास्तव ने जीत दर्ज की। यज्ञमणि और सौरभ इनके पीछे थे।

बार एसोसिएशन के चुनाव में कैसरबाग के परिसर में बुधवार को मतदान हुआ था। कुल 3672 में से 2722 वकीलों ने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बार चुनाव में पहली बार महिला आरक्षण लागू किया गया। 22 पदों के लिए 116 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें कोषाध्यक्ष समेत कुल सात पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। कोषाध्यक्ष पद पर चार महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ीं। वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकारिणी में भी महिलाओं के लिए तीन-तीन सीटें सुरक्षित थीं।

अध्यक्षः जी एन शुक्ला चच्चू 1255 मत, सुरेश पाण्डेय 1136 मत,राजेंद्र शर्मा 115 मत व परशुराम मिश्र 98 मत।

महामंत्रीः जितेंद्र यादव जीतू 1094 मत, आदर्श मिश्रा 846 मत, कुलदीप वर्मा 568 मत, मारुत शर्मा 111 मत व कामिनी ओझा 23 मत।

वरिष्ठ उपाध्यक्षः मनीष श्रीवास्तव 556 मत, यज्ञमणि 424 मत, कमल किशोर 369 मत व सौरभ 357 मत।

बताते चलें कि शुक्रवार को 2722 मतों में से 1500 मतों की गिनती की जा सकी थी। वहीं, शनिवार को अध्यक्ष, महासचिव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर शेष 1222 मतों की गिनती की गई। गिनती के बाद तीन पदों के विजेताओं की घोषणा की गई। इसमें अध्यक्ष पद पर गोविंद नारायण शुक्ला को 1255वोट मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी सुरेश पांडेय को 1136 जबकि राजेंद्र शर्मा को 115 और परशुराम मिश्रा को 98 वोट मिले। महासचिव पद पर जितेंद्र यादव 1094 वोट पाकर विजयी हुए। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी आदर्श मिश्रा को 846, कुलदीप वर्मा को 568, मारुत शर्मा को 111 और कामिनी शर्मा को मात्र 23 वोट ही प्राप्त हुए। चुनाव अधिकारी ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मनीष श्रीवास्तव को निर्वाचित घोषित किया। उन्होंने बताया कि मनीष श्रीवास्तव को 556 वोट मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी यज्ञमणि दीक्षित को 424 वोट मिले। इस पद पर अपना भाग्य आजमा रहे कमल किशोर को 369 और सौरभ को 357 मत पाकर संतोष करना पड़ा। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष, महासचिव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के विजेताओं की घोषणा के बाद अब शेष पदाधिकारियों और कार्यकारी सदस्यों के मतों की गिनती की जाएगी।

अखिलेश यादव का गंभीर आरोप, कहा- बीजेपी की लखनऊ पदयात्रा में आई महिलाओं को सड़ा खाना खिलाया

लखनऊ, (जीएनएस)।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की पदयात्रा पर गंभीर आरोप लगाया है. वढ के पूर्व सीएम ने दावा किया है कि जिन महिलाओं को पदयात्रा में बुलाया गया उन्हें पता ही नहीं था कि किस लिए बुलाया गया है. उन्हें जबरदस्ती बुलाया गया था.

राजधानी लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय पर अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि महिलाओं को बुलाकर उन्हें सड़ा खाना खिलाया गया. अखिलेश ने तंजिया लहजे में कहा कि लखनऊ आईं महिलाएं खोज रहीं थीं कि उन्हें आवास कौन देगा.

महाराष्ट्र की राह पर यूपी में भी अक्टक्ट! इस बयान से मच सकता है हंगामा, कहा- एक दिन आएगा जब...

इससे पहले कन्नौज सांसद ने पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका समाज के प्रति योगदान हमेशा याद रखा जाएगा.

उन्होंने कहा कि पूरे जीवन का आकलन करें तो अजीज कुरैशी गंगा-जमुनी तहजीब के बड़े पुरोधा रहे और भारतीयता व हिंदुस्तानियत को आगे बढ़ाने का काम किया. अखिलेश यादव ने उनके व्यक्तित्व को सिद्धांतवादी बताते हुए कहा कि उन्होंने जीवनभर सेक्युलर फैब्रिक को मजबूत किया और बड़े फैसले लेने से कभी पीछे नहीं हटे, जैसे लखनऊ आने के बाद रामपुर में बनी यूनिवर्सिटी का एक्ट पास कराना.

वढ ढङ्घ'३ू२ः सीएम योगी के लिए बीजेपी चीफ नितिन नवीन के ऐलान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा- वो वोट जब...

गाजीपुर और हाथरस प्रकरण का किया जिक्र

इस दौरान उन्होंने गाजीपुर और हाथरस प्रकरण का जिक्र करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि हाथरस मामले में पीड़िता की अंतिम इच्छा तक पूरी नहीं होने दी गई, जबकि उन्होंने खुद डीएम से इस बारे में बात की थी. उन्होंने कहा कि सरकार को किसी से कोई लेना-देना नहीं है और मीडिया पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कई चैनलों को पिछले 10 साल में भारी फंडिंग मिली. अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है और 'बब्बर शेर' की छवि को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है.

लखनऊ में 870 करोड़ के शहरी विकास प्रस्ताव, अर्बन प्लाजा, शूटिंग रेंज और कूड़ा बिजली प्लांट

लखनऊ नगर निगम ने केंद्र सरकार की अर्बन चैलेंज फंड स्कीम के तहत 870 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया है।

लखनऊ। (जीएनएस)। केंद्र सरकार की अर्बन चैलेंज फंड स्कीम के तहत नगर निगम ने 870 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया है। पहले केवल लालबाग में नगर निगम के बालाकदर कार्यालय की भूमि पर अर्बन प्लाजा बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन अब इसमें दो अन्य योजनाएं भी शामिल की गई हैं।

नगर विकास विभाग को भेजे गए इन प्रस्तावों को शुक्रवार को नगर विकास की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इनमें से एक योजना सरोजनीनगर में स्थित शूटिंग रेंज को अंतरराष्ट्रीय मानक का बनाने की है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

नगर निगम के मुख्य अभियंता (सिविल) महेश चंद्र वर्मा ने बताया कि नगर निगम अर्बन चैलेंज फंड से तीन योजनाओं को लाने की तैयारी कर रहा है। इनमें अर्बन प्लाजा, शूटिंग रेंज का जीर्णोद्धार और शिवरी में कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट शामिल हैं। जिन प्रस्तावों को स्वीकृति मिलेगी, उनकी विस्तृत कार्ययोजना (डीपीआर) तैयार की जाएगी।

कूड़े से बिजली प्लांट के लिए छह सौ करोड़ की योजना

मोहान रोड शिवरी में कूड़ा प्रबंधन के प्लांट के पास कूड़े से बिजली

बनाने की योजना थी, लेकिन बजट की कमी के कारण आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। अर्बन चैलेंज फंड स्कीम के तहत 600 करोड़ की योजना तैयार की जाएगी। शहर से प्रतिदिन 1800 से 1900 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है, लेकिन कूड़े के मिश्रण के कारण इसे बिजली बनाने में उपयोग करना चुनौतीपूर्ण है।

इससे पहले, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में लखनऊ में कूड़े से बिजली बनाने की योजना का प्रस्ताव रखा था। हरदोई रोड पर 88 करोड़ रुपये की लागत से एक प्लांट भी स्थापित किया गया था, लेकिन वह बिना बिजली बनाए ही बंद हो गया। अधिकारियों का दावा है कि नई तकनीक से कूड़े की छंटाई की जाएगी, जिससे बिजली उत्पादन संभव हो सकेगा।

अर्बन चैलेंज फंड स्कीम का विवरण

अर्बन चैलेंज फंड स्कीम के अंतर्गत किसी भी परियोजना की लागत का 25 प्रतिशत केंद्र सरकार, 50 प्रतिशत बाजार से जुटाई गई राशि, नगर निगम बांड, ऋण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी से प्राप्त किया जाएगा। शेष 25 प्रतिशत राशि निकायों को अपनी आय से खर्च करनी होगी।

नगर आयुक्तों के साथ हाल ही में हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में अर्बन चैलेंज फंड स्कीम के लिए प्रस्ताव देने के निर्देश दिए गए थे। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने लालबाग के बालाकदर की भूमि पर अर्बन प्लाजा बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब तीन प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।

शूटिंग रेंज के जीर्णोद्धार के लिए 200 करोड़ अमौसी गांव में लगभग डेढ़ दशक पहले स्थापित शूटिंग रेंज का जीर्णोद्धार भी अर्बन चैलेंज फंड स्कीम के तहत किया जाएगा। इसके लिए 197 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च है। 41.60 एकड़ भूमि में बने इस शूटिंग रेंज का जीर्णोद्धार निजी सहभागिता से किया जाएगा। इसके लिए एलडीए को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

नगर निगम ने 15 अप्रैल को प्रस्ताव पारित किया था कि भूमि का पुनर्ग्रहण एलडीए के पक्ष में किया जाएगा। इस परियोजना में 20 एकड़ में अत्याधुनिक शूटिंग रेंज का विकास किया जाएगा, जबकि शेष भूमि पर टाउनशिप के लिए पांच भूखंड और एक होटल बनाने की योजना है। नगर निगम अब अर्बन चैलेंज फंड से शूटिंग रेंज का जीर्णोद्धार स्वयं करने की तैयारी कर रहा है।

चार मंजिला होगा अर्बन प्लाजा

लालबाग में नगर निगम का बालाकदर कार्यालय स्थित है, जहां मार्ग प्रकाश, वर्कशाप और स्टोर हैं। 4750 वर्ग मीटर की यह भूमि प्राइम लोकेशन पर है। यहां चार मंजिला अर्बन प्लाजा बनाने की योजना है, जिसमें कार्यालयों के साथ व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन भी संभव होगा। इसके साथ ही पार्किंग की सुविधा और अन्य कार्यों के माध्यम से आय बढ़ाने की योजना है। इस परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपये का बजट अर्बन चैलेंज फंड से प्राप्त किया जाएगा।

मजारों पर बुलडोजर: लखनऊ केजीएमयू में छः मजार अवैध ; दो बार नोटिस के बाद भी नहीं दिए दस्तावेज

सुनवाई पूरी हो चुकी, जल्द ही अंतिम आदेश यानी स्पीकिंग ऑर्डर जारी होगा.

लखनऊः (जीएनएस)। राजधानी के प्रसिद्ध किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) परिसर में अवैध मजारों को हटाने की बड़ी कार्रवाई होने जा रही है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन मजारों को अवैध बताते हुए हटाने का फैसला किया है. परिसर में करीब छह से ज्यादा मजारें हैं, जिन्हें हटाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है. KGMU प्रशासन का कहना है कि इन निमार्णों पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार दो बार नोटिस जारी किए गए और पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन किसी भी पक्ष ने मालिकाना हक साबित करने वाले दस्तावेज नहीं पेश किए. न तो कोई केयरटेकर सामने आया और न ही कोई वैध कागजात दिए गए. अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और जल्द ही अंतिम आदेश यानी स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया जाएगा.

केजीएमयू में बनी मजारों को प्रशासन ने अवैध बताया है.

केजीएमयू में बनी मजारों को प्रशासन ने अवैध बताया है.

इसके बाद बुलडोजर से कार्रवाई शुरू हो जाएगी. KGMU प्रवक्ता प्रोफेसर केके सिंह ने कहा, हमने दो मौके दिए थे. कोई नहीं आया, कोई दस्तावेज नहीं दिया. प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.अगले दो दिन में आदेश के बाद कार्रवाई करेंगे. दूसरी ओर, मजारों से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई. वे प्रशासन के फैसले को मानने की बात कह रहे हैं.

कैंपस के एमबीबीएस छात्र रोहित यादव ने कहा, मेडिकल संस्थान में ऐसे निर्माण नहीं होने चाहिए थे. अगर नोटिस दिया गया था तो समय रहते हट जाना चाहिए था.अब कार्रवाई हो रही है तो जिम्मेदार खुद हैं. इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है. समाजवादी पार्टी की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि भाजपा इसे अवैध निर्माण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन बता रही है. भाजपा प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा कि अवैध निर्माण हटाना जरूरी है और यह कार्रवाई नियमों के अनुसार हो रही है.

KGMU लखनऊ का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल संस्थान है, जहां हजारों छात्र पढ़ते हैं और मरीजों का इलाज होता है. प्रशासन का मानना है कि परिसर को साफ-सुथरा और अतिक्रमण मुक्त रखना जरूरी है. फिलहाल सबकी नजर स्पीकिंग ऑर्डर पर है, जिसके बाद तय होगा कि बुलडोजर कब चलेगा.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का चंडीगढ़ में राष्ट्रीय चिंतन शिविर, दूसरे दिन राज्यों और केंद्र के बीच गहन चर्चा के साथ 'विजन से एक्शन' की ओर बढ़े कदम

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार चिंतन शिविर के दूसरे दिन के सत्रों में हुए शामिल, केंद्र और राज्यों के बीच गहन विचार-विमर्श पर रहा जोर

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने राष्ट्रीय चिंतन शिविर में दूसरे दिन के विचार-विमर्श को "सार्थक और व्यावहारिक अनुभव पर आधारित" बताया

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा के नेतृत्व में सुबह के योग सत्र के साथ चिंतन शिविर के दूसरे दिन की शुरूआत हुई, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विषय-आधारित चचाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ

पाँच अलग-अलग समूहों ने छात्रवृत्ति सुधार, नशामुक्त भारत, श्रम की गरिमा, सम्मानजनक वृद्धावस्था और दिव्यांग बच्चों की प्रारंभिक पहचान एवं सहायता जैसे विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया

(जीएनएस)।

"अंत्योदय का संकल्प, अमृत काल का प्रतिबिंब झ विकसित भारत @2047" विषय पर आधारित तीन दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आज चंडीगढ़ में दूसरा दिन रहा। चंडीगढ़ में आयोजित इस शिविर के दूसरे दिन का मुख्य फोकस सामुदायिक जुड़ाव को मजबूत करने, सार्वजनिक-निजी-जन भागीदारी को बढ़ावा देने और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से सामाजिक न्याय योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने पर रहा। समावेशी और जवाबदेह गवर्नेंस पर उद्घाटन सत्र के दौरान दिए गए जोर को आगे बढ़ाते हुए, आज के विचार-विमर्श में देश भर से मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने एक साथ मिलकर समयबद्ध और कार्यान्वयन योग्य समाधानों पर काम किया। इस सत्र का उद्देश्य गवर्नेंस की पारदर्शिता को बढ़ाना और ऐसी नीतियों को धरातल पर उतारना है जो विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में सहायक हों।

दिन की शुरूआत एक संयुक्त योग सत्र के साथ हुई, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों और अन्य प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस सत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने अन्य गणमान्य

व्यक्तियों के साथ सहभागिता की। इस कार्यक्रम ने दिनभर की कार्यवाही के लिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और सहभागिता का वातावरण तैयार किया तथा सामाजिक न्याय की सेवाओं को प्रदान करने में मंत्रालय के समग्र और व्यक्ति-केंद्रित दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

'सामुदायिक सहभागिता का लाभ उठाना और बेहतर सामाजिक न्याय वितरण हेतु सार्वजनिक-निजी-जन भागीदारी (पीपीपीपी) मॉडल की संभावनाएं तलाशना' विषय पर आयोजित थीमैटिक ब्रेकफास्ट के दौरान प्रतिभागियों ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज संगठन और निजी क्षेत्र के संस्थान सबसे वंचित वर्गों तक पहुँचने के लिए सरकारी प्रयासों के पूरक बन सकते हैं। इस संवाद में ऐसे व्यावहारिक पीपीपीपी मॉडलों पर प्रकाश डाला गया जो नशामुक्ति, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, छात्रवृत्ति वितरण, स्वच्छता कर्मियों को सहायता और कमजोर वर्गों के पुनर्वास जैसे कार्यों को और अधिक सशक्त बना सकते हैं।

दूसरे दिन के सत्रों के दौरान, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार कार्यवाही में शामिल हुए और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हो रही विषय-आधारित चचाओं का बारीकी से अवलोकन किया। शिविर के समग्र उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने इस बात को दोहराया कि सामाजिक क्षेत्र में 'विकसित भारत @2047' का विजन पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए गरिमा, सुलभता और निरंतरता के तीन स्तंभों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस विचार-विमर्श का मुख्य उद्देश्य 'कल्याण से सशक्तिकरण' की ओर बढ़ना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह तभी संभव है जब कागजों पर स्वीकृत लाभ विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और अन्य वंचित समूहों के लिए धरातल पर निर्बाध और उपयोगकर्ता के अनुकूल सेवाओं के रूप में परिवर्तित हों।

चिंतन शिविर की प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए, सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) श्री सुधांश पंत ने बताया कि इस शिविर के लिए दस प्रमुख विषयों की पहचान की गई है—जिनमें से सात सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से और तीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) से संबंधित हैं। चर्चा को प्रभावी बनाने के लिए प्रतिभागियों को पाँच विषय-आधारित समूहों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक समूह का मार्गदर्शन एक लीड कोऑर्डिनेटर और रैपोर्टियर कर रहे हैं। इन समूहों का उद्देश्य सामान्य चर्चा के बजाय ऐसे संक्षिप्त प्रेजेंटेशन तैयार करना है, जिनमें मुख्य नीतिगत मुद्दे, क्रियान्वयन में आने वाली कमियाँ, सर्वोत्तम कार्यप्रणाली और समय-सीमा के साथ स्पष्ट कार्य-बिंदु शामिल हों।

दूसरे दिन के ब्रेकआउट सत्र के दौरान, पाँच विषय-आधारित समूहों ने 'विकसित भारत 2047' रूपरेखा के तहत अपने विषयों के पहले सेट पर विस्तृत चर्चा की।

समूह-I ने 'शिक्षा से समृद्धिः छात्रवृत्ति वितरण और शैक्षिक पहुंच का सुदृढ़ीकरण' विषय पर चर्चा की। इस चर्चा का मुख्य केंद्र छात्रवृत्ति तक समयबद्ध और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इसके समान क्रियान्वयन, सत्यापन और वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाना, शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार और छात्रों के समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना रहा।

समूह-II ने 'नशामुक्त भारतः नशामुक्ति और पुनर्वास इकोसिस्टम का सुदृढ़ीकरण' विषय पर कार्य किया। इस दौरान उपचार और पुनर्वास सुविधाओं के विस्तार, डिजिटल निगरानी, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और समुदाय-आधारित आउटरीच (जनसंपर्क) बढ़ाने पर विस्तार से विचार किया गया।

समूह-III ने 'श्रम की गरिमा : डिग्निटी इन लेबर' विषय पर विचार-विमर्श किया। इसमें मैनहोल से मशीन-होल प्रणाली की ओर बढ़ने (मैन्युअल सफाई की जगह मशीनी सफाई), स्वच्छता कार्यों के दौरान शून्य मृत्यु दर सुनिश्चित करने के लक्ष्य (मिशन जीरो) और स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा, गरिमा तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

महिलाओं में प्री-मेनोपॉज सिम्प्टम्स का दिल की बीमारी से सीधा कनेक्शन

महिलाओं को प्री-मेनोपॉज की शुरूआत होते ही सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि इस दौरान हार्मोन लेवल एस्ट्रोजन कम होने लगता है। इसका सीधा असर दिल, सांस और बीपी आदि पर पड़ता है। ऐसे में, 45 की उम्र के बाद अगर मूड स्विंग, नाइट स्वेट्स (रात में पसीना आना) और स्लीप पैटर्न में बदलाव होता है तो तुरंत कार्डिएक टेस्ट करवाना चाहिए।

लखनऊ , (जीएनएस)। महिलाओं को प्री-मेनोपॉज की शुरूआत होते ही सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि इस दौरान हार्मोन लेवल एस्ट्रोजन कम होने लगता है। इसका सीधा असर दिल, सांस और बीपी आदि पर पड़ता है। ऐसे में, 45 की उम्र के बाद अगर मूड स्विंग, नाइट स्वेट्स (रात में पसीना आना) और स्लीप पैटर्न में बदलाव होता है तो तुरंत कार्डिएक टेस्ट करवाना चाहिए। ये लक्षण आपके दिल पर सीधा असर डालते हैं। ये फैक्ट्स लोहिया संस्थान के ऑब्स एंड गाएनी विभाग द्वारा की गई स्टडी में सामने आये हैं। यह स्टडी जर्नल ऑफ मिड लाइफ हेल्थ में पब्लिश हुई है।

सिम्प्टम्स का दिल पर डायरेक्ट असर

ऑब्स एंड गाएनी विभाग की हेड डॉ। नीतू सिंह ने बताया प्री-मेनोपॉज में होने वाले वासोमोटर सिम्प्टम्स और कार्डिएक ऑटोनॉमिक फंक्शन में डायरेक्ट कनेक्शन देखने के लिए स्टडी की गई। 45 से 50 वर्ष की 200 महिलाओं को इस स्टडी में शामिल किया गया। यहां उनके वासोमोटर सिम्प्टम्स यानि मूड स्विंग, नाइट स्वेट्स, स्लीप पैटर्न आदि का कार्डिएक ऑटोनॉमिक फंक्शन यानि हार्ट रेट, हार्ट वर्किंग टाइप और हार्ट रेट रिस्पांस टू ब्रीथिंग आदि में क्या कनेक्शन है, के लिए मरीजों का ईसीजी, बीपी चेकअप आदि टेस्ट से सभी पैरामीटर को देखा गया। जिसमें पाया गया कि प्री-मेनोपॉजल सिम्प्टम्स का हार्ट से डायरेक्ट कनेक्शन है।

डॉ। नीतू सिंह ने बताया कि स्टडी में पाया गया प्री-मेनोपॉजल सिम्प्टम्स आने पर महिलाओं पर कार्डिएक वैस्कुलर रिस्क कई गुना बढ़ सकता है यानि प्री-मेनोपॉजल स्टेज शुरू होने पर ये लक्षण आएं तो अपना कार्डिएक असेसमेंट करवाना चाहिए ताकि समय रहते किसी भी हार्ट रिलेटेड बीमारी का पता लगाया जा सके और उसका सही से ट्रीटमेंट किया जा सके। इस दौरान सभी हार्मोन का लेवल घटता रहता है। खासतौर पर एस्ट्रोजन हार्मोन के कम होने से दिल को मिलने वाली सुरक्षा कम हो जाती है।

आजकल की खराब लाइफस्टाइल, खराब फूडिंग, एक्सरसाइज न करना, अल्कोहल व स्मोकिंग महिलाओं में काफी बढ़ गया है। जिसकी वजह से महिलाओं में मेनोपॉज समय से पहले आ रहा है। पहले 55 की उम्र के बाद यह देखने को मिलता था, लेकिन अब यह 40 की उम्र के बाद ही देखने को मिल रहा है, जो चिंता की बात है। इसकी वजह से महिलाओं में हेल्थ रिलेटेड समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में, हेल्दी लाइफस्टाइल, पोषण युक्त खाना, जंक फूड से दूरी और एक्सरसाइज आदि जरूरी है।

45 की उम्र के बाद प्री-मेनोपॉजल सिम्प्टम्स आने पर कार्डिएक असेसमेंट जरूर करवाना चाहिए ताकि समय रहते दिल की बीमारी का पता लगाकर उसका ट्रीटमेंट किया जा सके।- डॉ। नीतू सिंह, लोहिया संस्थान